

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग

देहरादून दिनांक : 02 अगस्त, 2016

विषय :- शिवपुरी में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा-कार्यालय भवन/स्टोर/डोरमैट्री/क्लास रूम/किचन/शौचालय/स्टाफ कक्ष इत्यादि के निर्माण हेतु प्राविधानित बजटीय धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-738/दो-लेखा-2869/2016-17 दिनांक 23.08.16 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिवपुरी में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा-कार्यालय भवन/स्टोर/डोरमैट्री/क्लास रूम/किचन/शौचालय/स्टाफ कक्ष इत्यादि के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-235/VI-2/2016-52(01)16 दिनांक 30.03.16 के द्वारा धनराशि रु० 80.00 लाख उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस हेतु प्राविधानित बजटीय धनराशि रु० 10.00 लाख (दस लाख) मात्र को द्वितीय किश्त के रूप में आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं०-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या-490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 तथा शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

4- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

5- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

6- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन केवल अपरीहार्य स्थिति की दशा में ही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

8- यदि उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत है, तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाए।

9- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

अथवा.....

- 10- अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 11- कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
- 12- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 13- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-00-15-प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का व्यवसायिक प्रशिक्षण-25-लघु निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

527
पृष्ठांकन संख्या- (1)/VI-2/2016-52(1)16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव